

प्रधानमंत्री की पहलों के कारण 25 करोड़ लोग गरीबी से उबरे- भजनलाल

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी विज्ञान से शासन, विकास व जन कल्याण के नये प्रतिमान बने

जयपुर, 13 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सेवा, सुशासन और लोक कल्याण को समर्पित गौरवशाली 12 वर्ष का कार्यकाल के पूर्ण होने पर शनिवार को मीडिया से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सबसे लम्बे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की असाधारण उपलब्धि हासिल की है। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

मीडिया संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले यूपीए सरकार में हमारा देश भ्रष्टाचार, महंगाई, अरांतकवाद, नक्सलवाद, नीतिगत अस्थिरता और खराब आर्थिक हालात जैसी अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था। ऐसे समय पर प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी संभाली और देश को इन चुनौतियों से बाहर निकाला तथा अपने दूरदर्शी विज्ञान से 12 वर्षों में शासन, विकास और जनकल्याण के अनेक नए प्रतिमान स्थापित किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त राशन की सुविधा मिली और 60 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भरोसा। प्रधानमंत्री की इन्हीं पहलों का बदौलत 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से उबर पाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युवा शक्ति को भारत की



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल के पूर्ण होने पर मीडिया से संवाद किया।

सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में 12 जून से 20 जून तक हर जिले में जन कल्याण शिविरों का आयोजन कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास से संबंधित सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध

करवाई जा रही हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के साथ राजस्थान में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। प्रदेश में युवाओं को पेंपर लीक जैसी समस्याओं से राहत मिली है। केन्द्र और राज्य सरकार का लक्ष्य विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और विकसित भारत के संकलन को साकार करना है। इस दौरान "12 साल विकास

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केन्द्र में मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान के हर जिले में 12 से 20 जून तक जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इनमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, ग्रामीण विकास, पंचायतीराज, महिला व बाल विकास से संबंधित सेवाएं एक छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही हैं।**

के, विश्वास के और जनकल्याण के" अभियान के प्रदेश संयोजक भूपेन्द्र सैनी, भाजपा प्रदेश महामंत्री ब्रजेश सिंह बग्डी, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रमोद वशिष्ठ, भाजपा मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा, विधायक एवं प्रवक्ता कुलदीप घनकड सहित, भाजपा पदाधिकारी उपस्थित थे।

अवैध कोयला खदान में दम घुटने से चार की मौत

रामगढ़, 13 जून। रामगढ़ जिले के सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) के अरगाड्डा क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जंगल क्षेत्र में बने एक अवैध कोयला मुहाने (चाल) में फंसने से चार मजदूरों की मौत हो गई। यह घटना अरगाड्डा पुराने माईस के सामने स्थित चपरी गांव के काजू बागान क्षेत्र में हुई। शनिवार को पुलिस और माईस रेस्क्यू

■ **पुलिस और माइन्स रेस्क्यू टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर चारों मजदूरों के शव बाहर निकाले।**

टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर चारों मजदूरों के शव बाहर निकाले। मृतकों की पहचान किशोर, आशोष, देवा और डब्लू के रूप में हुई है। सभी मजदूर अवैध रूप से कोयला निकालने के लिए खदाननुमा खनन में उदरे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अंदर ऑक्सीजन की भारी कमी होने के कारण उनका दम घुट गया और वे बाहर नहीं निकल सके।

घटना की सूचना मिलने के बाद, रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे, कुज्जू ओपी प्रभारी आशुतोष कुमार सिंह सहित, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। इसके बाद माईस रेस्क्यू की 12 सदस्यीय टीम को बचाव अभियान में लगाया गया। काफी मशक्कत के बाद सभी शवों को बाहर निकाला गया।

अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर अभी भी भारी सस्पेंस

एक अमेरिकन अधिकारी ने कहा, डील होने की संभावना 75 से बढ़कर 80 से 85 प्रतिशत पहुंच गई है

-जाल खंबा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 जून। अमेरिका-ईरान शांति समझौते को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। वॉशिंगटन के एक अधिकारी ने कहा है कि समझौते तक पहुंचने को लेकर उनका भरोसा 75 प्रतिशत से बढ़कर 80-85 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, तेहरान की ओर से परमाणु मंडार, फ्रीज की गई संपत्ति और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे प्रमुख मुद्दों पर सहमति को लेकर अभी भी खूब लड़ना बाकी है।

नाम न बताने की शर्त पर एक अमेरिकी अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि ईरान के साथ संभावित समझौते की रूपरेखा पर "अगले कुछ दिनों" में हस्ताक्षर होने की संभावना है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि समझौता अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है। हस्ताक्षर की तारीख या स्थान अभी स्पष्ट नहीं है। अधिकारी ने कहा कि ईरान में अंदरूनी फैसले लेने की प्रक्रिया "बहुत जटिल" है।

वाइट हाउस के अधिकारी ने कहा, "यह समझौता असल में बहुत सीधा-सादा है। यह उन मुख्य उद्देश्यों को पूरा करता है, जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस मिशन के लिए निर्धारित किया था और अंत में जो हमें बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा है। सबसे पहले, इससे जलदमरूमध्य फिर से खुल जाएगा और नाकाबंदी समाप्त

■ **नाम नहीं बताने की शर्त पर एक अमेरिकन अफसर ने कहा कि संभावित समझौता हालांकि पूरा नहीं बना है, पर, उस पर अगले कुछ दिनों में हस्ताक्षर हो सकते हैं, लेकिन जगह अभी तय नहीं है।**

■ **समझौते में सबसे बड़ा अवरोध ईरान की शर्तें हैं, वह न केवल परमाणु कार्यक्रम को चालू रखना चाहता है, बल्कि फ्रीज संपत्ति की वापसी, होमुज स्ट्रेट पर आंशिक नियंत्रण भी चाहता है।**

होगी। दूसरा, इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त किया जाएगा। तीसरा, इससे अमेरिका को समृद्ध परमाणु सामग्री प्राप्त होगी। हमने यह व्यवस्था की है कि इस सामग्री को वहीं नष्ट किया जाएगा और उसके बाद देश से बाहर ले जाया जाएगा।"

ईरान को तुरंत आर्थिक लाभ मिलने की खबरों को खारिज करते हुए अधिकारी ने कहा कि मेमोरैंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग (एमओयू) पर हस्ताक्षर होते ही तेहरान को कोई धुम्रतान नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, "मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि एमओयू पर हस्ताक्षर के साथ ईरान को 12 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर का 6 अरब डॉलर मिलेंगे। यह पूरी तरह गलत है। एमओयू पर हस्ताक्षर होते ही या केवल बातचीत के आधार पर ईरान को कुछ नहीं मिलेगा।"

अधिकारी ने आगे कहा, "ईरान को जो आर्थिक लाभ मिलेगा, वह

समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने का आर्थिक इनाम है। इसलिए अगर वह वादे के मुताबिक परमाणु सामग्री सौंपता है, तो उसे कुछ लाभ मिलेगा। यदि वह अपने परमाणु कार्यक्रम या परमाणु सुविधाओं को समाप्त करता है, तो उसे अतिरिक्त लाभ मिलेगा। और यदि वह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता दिखाता है, तो उसे इसके अलावा भी और लाभ मिल सकते हैं।"

हालांकि इस प्रस्तावित समझौते को एक बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश किया जा रहा है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार, ईरानी पक्ष का कहना है कि यह समझौता केवल 60 दिनों के युद्धविरोध की व्यवस्था करेगा। इसके बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम और तेहरान की फ्रीज की गई सम्पत्ति को लेकर एक और दौर की बातचीत होगी।

ममता बनर्जी के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
हो गया है कि उनकी पत्नी, जो एक निर्वाचित विधायक हैं, भी ऋतुबत बनर्जी के नेतृत्व वाले राज्य स्तरीय बागी गुट में शामिल हो जाएंगी। इससे विद्रोही विधायकों की कुल संख्या 80 तुणमूल विधायकों में से 65 तक पहुंच जाएगी।

दूसरी ओर, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आलोचना का स्वर लगातार तेज होता जा रहा है। अब आलोचनाएं उनके निजी सचिव सुमित रॉय पर भी केन्द्रित हो गई हैं। पुलिस सुमित रॉय की तलाश कर रही है, जिन पर संदेह है कि वे अभिषेक बनर्जी के घर में छिपे हुए थे।

सालबोनी में जमीन हड़पने के मामले की जांच के सिलसिले में सालबोनी पुलिस थाने की एक टीम रात को बच्चे आभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। पुलिस टीम को घर में प्रवेश पाने से पहले चार घंटे तक इंतजार करना पड़ा।

आशंका है कि सुमित रॉय की गिरफ्तारी और पृथलाख से अभिषेक के कामकाज से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं। जानकार सूत्रों का मानना है कि पदों के पीछे के सभी सौंदों को सुमित रॉय ही संभालते थे। यहां तक कि पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी कहा कि पुलिस को सुमित रॉय की भूमिका और गतिविधियों की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

सुमित रॉय का नाम गिरफ्तार किए गए तुणमूल कांग्रेस नेता सुजांय हाजरा ने लिया था। जमीन पर कब्जा करने और जमीन के प्लॉट के गलत इस्तेमाल के सिलसिले में सुमित और सुजांय के बीच कई करोड़ रुपयों का लेन-देन होने का बयान कही जा रही है। अब लागू हो रहा सुमित रॉय की भूमिका पर खुलकर बोल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि पुलिस टीम के पहुंचने के कुछ ही समय बाद ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची थीं।

असम के जोरहाट में वायु सेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, 5 जवान शहीद

भारतीय वायु सेना का एएन 32 परिवहन विमान लैंडिंग करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया

जोरहाट (असम), 13 जून। भारतीय वायुसेना (आईएएफ) का एक एएन-32 परिवहन विमान शुक्रवार को असम के जोरहाट स्थित रैरिया एयरफोर्स स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में वायु सेना के पांच कर्मी शहीद हो गये। विमान लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद उसमें आग लग गई।

भारतीय वायु सेना की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारतीय वायु सेना को असम के जोरहाट में एएन-32 विमान दुर्घटना में अपने पांच कर्मियों के निधन पर गहरा

■ **भारतीय वायु सेना ने घटना की पुष्टि की और हादसे की जांच के आदेश दिए।**

दुख है। हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, प्लानेट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सर्जेंट जितेन्द्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। भारतीय वायु सेना शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है

और दुख की इस घड़ी में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। रक्षा मंत्री राजनथा सिंह ने भी एक्स पोस्ट में घटना पर दुःख जताया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना के बाद एयरबेस क्षेत्र में आग की ऊंची लपटें और घना धुआं देखा गया। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान वायुसेना की 43वीं स्क्वाड्रन से संबंधित था और नियमित सैन्य उड़ान पर था। विमान का उपयोग सैन्य सामग्री और रसद के परिवहन के लिए किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि जोरहाट में एक एएन-32 विमान दुर्घटना का शिकार हुआ है।

परीक्षा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अधिकारियों के लिए तैयार किया गया है, जो एनटीई की विभिन्न परीक्षाओं, विशेषकर नोट (यूजी), के संचालन में शामिल रहते हैं। इस कार्यक्रम को परीक्षा से जुड़े अधिकारियों की क्षमता को मजबूत करने और ऑफलाइन, पेन-और-पेंपर आधारित परीक्षाओं को सुचारू, सुरक्षित और स्टैंडर्ड तरीके से आयोजित करने के लिए बनाया गया है।

कार्यक्रम में परीक्षा प्रक्रिया के पूरे चक्र को शामिल करते हुए चार माँड्यूल तैयार किए गए हैं। पहले माँड्यूल में नियुक्ति, पारदर्शिता और परीक्षा की शुचिता बनाए रखने में परीक्षा कर्मियों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे माँड्यूल में परीक्षा पूर्व तैयारियों, परीक्षा केंद्रों की तैयारी, सुरक्षा व्यवस्था और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के पालन से जुड़े पहलुओं को शामिल किया गया है।

‘अब भारत दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देगा’

नई दिल्ली, 13 जून। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और समुद्री खतरों से निपटने के लिए कई अत्याधुनिक तकनीकों का सफल परीक्षण किया। 10 और 11 जून को किए गए लगातार तीन परीक्षणों में भारत की मल्टी-लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) प्रणाली ने अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया।

जिससे भारत अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) श्रेणी के खतरों को भी हवा में मार गिराने

■ **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने मल्टी लेपर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का सफल परीक्षण किया**

में सक्षम हो गया है। इसके साथ ही, भारत दुनिया के उन चुनिंदा एलिट देशों की कतार में शामिल हो गया है। जिनके पास ऑपरेशनल स्तर की मिसाइल रक्षा क्षमता है। इस उपलब्धि के कारण अब भारत दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को तो भी हवा में ही नष्ट कर देगा।

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, 10 और 11 जून, 2026 को लगातार तीन फ्लाइट टेस्ट किए गए,

जिनमें मल्टी-लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (बीएमडी) सिस्टम का प्रदर्शन किया गया।

टेस्ट के दौरान, इंटरसेप्टर ने अपने टारगेट को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। इससे एडवांस्ड और नई टेक्नोलॉजी से बने लेयर्ड डिफेंस सिस्टम की असरदार क्षमता साबित हुई, जिसे बदलते मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है।

बीएमडी के सफल टेस्ट के अलावा, नेवल एंटी-शिप मिसाइल-मोडिफाई का पहला फ्लाइट टेस्ट भी सफलतापूर्वक किया गया। यह भारत की समुद्री स्ट्राइक और रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।

डीआरडीओ और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में यह उड़ान परीक्षण संपन्न हुआ। डीआरडीओ के चेयरमैन राजेश कुमार सिंह ने इस पूरी प्रक्रिया की बारीकी से समीक्षा की और इसमें शामिल सभी टीमों के तालमेल को सराहा।

उपेन्द्र कुशवाहा फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष बने

नई दिल्ली, 13 जून। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा को एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है।

शनिवार को दिल्ली के कांग्रेस ट्यूशन क्लब में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अधिवेशन के बाद सांठनिक चुनाव कार्यक्रम में सर्वसम्मति से पार्टी के संस्थापक एवं वरिष्ठ नेता उपेन्द्र कुशवाहा को आगामी कार्यकाल 2026-29 के लिए पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

मोदी का आज से यूरोप दौरा

■ **6 दिवसीय दौरे में प्र.मंत्री फ्रांस व स्लोवाकिया जाएंगे।**

नई दिल्ली, 13 जून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की छह दिवसीय महत्वपूर्ण आधिकारिक यात्रा शनिवार से शुरू हो गई है। उनकी यह यात्रा 18 जून को पूरी होगी।

अपनी रवानगी से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा के मुख्य उद्देश्यों और कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा करते हुए एक्स पर लिखा, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों और स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के निमंत्रण पर वे इस यात्रा पर जा रहे हैं।

फ्रांस की इस यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत के रणनीतिक विज्ञान में फ्रांस का खास

स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान हमारे संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला था। अब हम फरवरी के बाद हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।"

उन्होंने बताया कि 14 जून को वह और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत-इनेवेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारत-फ्रांस इनवेस्टिव वर्ष के तहत होने वाला यह आयोजन भारतीय स्टार्टअप

को वैश्विक निवेशकों से जोड़ेगा।

ले.जनरल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
रेगिस्तानी इलाके में एक आर्म्ड रेजिमेंट, पश्चिमी किशोर में एक आर्म्ड ब्रिगेड और जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद-विरोधी फोर्स की कमान शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उन्होंने भारतीय सेना के प्रमुख स्ट्राइक फॉर्मेशन में से एक सुदर्शन चक्र कॉर्प्स की कमान संभाली। इसके बाद उन्होंने दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के तौर पर काम किया।

एमएनआईटी, जयपुर पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
था, जबकि अंतिम तिथि 21 जुलाई 2023 थी। उसके प्रवेश पुस्तिका (नियम 4.6 और 4.7) के अनुसार, अंतिम तिथि के बाद फीस वापस नहीं की जा सकती, केवल 15,000 रुपये की कांशन मनी ही लौटाई जा सकती है। संस्थान का कहना था कि सीट खाली रह जाने से उसे आर्थिक नुकसान होगा। आयोग ने सबसे पहले यह जांच की कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत यह शिकायत सुनवाई योग्य है या नहीं, क्योंकि संस्थान ने आयोग के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था।

आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता ने कोई कक्षा अटेन्ड नहीं की थी, भौतिक पंजीकरण पूरा नहीं किया था और शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही प्रवेश वापस ले लिया था। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह विवाद शैक्षणिक मानकों से संबंधित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक नियमों के तहत अनुचित रूप से धन रोककर रखने से जुड़ा है। आयोग ने कहा कि जब कोई शैक्षणिक सेवा प्रदान ही नहीं की गई और छात्र ने सीट पर वास्तविक रूप से कब्जा भी नहीं किया, इस स्थिति में पूरी

फीस रोककर रखना अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस और प्रशासनिक कमी माना जाएगा। आयोग ने यूजीसी दिशानिर्देशों से छूट मिलने संबंधी संस्थान के दावे को भी खारिज कर दिया। आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में उच्च शिक्षा का सर्वोच्च नियामक निकाय है और उसके निर्देश सभी संस्थानों पर समान रूप से लागू होते हैं।

शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए यूजीसी ने एक अनिवार्य सार्वजनिक सूचना जारी कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 30 सितंबर 2023 तक किए गए प्रवेश निस्तीकरण (कैंसिलेशन) पर पूरी फीस वापस करने का निर्देश दिया था।

चूंकि शिकायतकर्ता ने 1 अगस्त 2023 को प्रवेश वापस लेने का आवेदन किया था, इसलिए उसका अनुरोध निर्धारित समय सीमा के भीतर था।

आयोग ने आगे कहा कि छात्रों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए बनाए गए राष्ट्रीय नियामक दिशानिर्देशों की किसी संस्थान के आंतरिक नियम या प्रॉस्पेक्टस की शर्तें निरस्त नहीं कर सकती।

नाबालिग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
नहीं आया, जिससे उसकी विश्वसनीयता पर संदेह किया जा सके। विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 6 नवंबर, 2022 को शाहपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि पिता को अभियुक्त अमित उसकी बेटी से दुष्कर्म कर रहा था, जिसे मौके पर परिजनों ने पकड़ लिया था। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को पता चला कि दुष्कर्म अभियुक्त ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना के कुछ माह पहले कपडों की दुकान के ट्रायल रूम में अभियुक्त ने उसका वीडियो बनाया था, जिसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर उससे साथ दुष्कर्म किया जा रहा था। दूसरी ओर बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि पीड़ित पक्ष ने वसूली के लिए मामला दर्ज कराया है। पहले भी पीड़ित पक्ष ने एक पॉक्सो का मामला दर्ज कराया था। जिसमें राजनीतिका कर लिया था। दोनों पक्षों को इससे के बाद अदालत ने अभियुक्तों को सजा सुनाई है।

आयोग ने सीट खाली रहने से आर्थिक नुकसान होने संबंधी संस्थान के तर्कों को भी अस्वीकार कर दिया। आयोग ने कहा कि भौतिक उपस्थिति और पंजीकरण की प्रक्रिया 1 अगस्त 2023 को होनी थी, जबकि कक्षाएं 7 अगस्त 2023 से शुरू होनी थीं। इसका अर्थ है कि खाली सीट भरने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध था। आयोग ने यह भी कहा कि प्रतिष्ठित संस्थानों में सामान्यतः लंबी प्रतीक्षा सूची होती है, लेकिन संस्थान यह दिखाए हैं कि वे इनके लिए उचित धन दे रहे हैं। आयोग ने संस्थान को सेवा में कमी और अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस का दोषी ठहराया। उसने संस्थान को आदेश दिया कि वह आदेश प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर 94,315 रुपये की पूरी राशि वापस करे। यदि संस्थान आदेश का पालन नहीं करता, तो उसे शिकायत दायर होने की तारीख से लेकर पूरी राशि चुकाने तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इसके अतिरिक्त, संस्थान को मानसिक उपपीडन के लिए 10,000 रुपये तथा मुकदमेबाजी के खर्च के लिए 15,000 रुपये का धुगतान भी करना होगा।